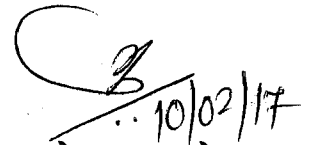


समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण),
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

शासन द्वारा सीजन वर्ष 2016-17 के लिए ईट भट्टा समाधान योजना लागू की गयी है, जिसमें 30 प्रतिशत समाधान राशि सहित प्रार्थना पत्र दिये जाने की अंतिम तिथि 20.01.2017 निर्धारित की गयी थी तथा उक्त तिथि के पश्चात् 30 दिन के अन्दर इस अवधि के लिये देय समाधान राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करके समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब भी इसे स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

उपर्युक्त समाधान योजना की समीक्षा पर पाया गया कि दिनांक 03.02.2017 तक कुल कार्यरत 16895 ईट भट्टों में से मात्र 7438 ईट भट्टों द्वारा ही समाधान योजना अपनायी गयी है । गाजियाबाद प्रथम व द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर, आगरा एवं मेरठ जोन में कार्यरत ईट भट्टों में से 30 प्रतिशत से भी कम ईट भट्टों द्वारा समाधान योजना अपनायी गयी है । यह स्थिति नितांत खेदजनक है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिक्षेत्र के सभी ईट भट्टों से ब्याज सहित देय समाधान राशि जमा कराते हुए समाधान प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2017 से पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करें तथा जिन कर निर्धारण अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में समाधान योजना न अपनाने वाले ईट भट्टों की संख्या अधिक पायी जाएगी, उनके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।


10/02/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।